

4

कुल
होशंगाबाद
जुला

2017
इ.

मास-जुलै/16
28-11-17
28-11

1. प्रिंशत कुमार आठो भुंराम जाट
PBR/किंगरजी/होशंगाबाद/शुक्र/2017/4948

2. भुंराम आठो हरीशंकर जाट

दोनो निवासी ग्राम गुराडिया जाट ,

तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद ----- अमीलाधीर्ण /

पुनरीक्षणकीर्ण

बनाम

1. हरी आठो गौडिया

निवासी बासनिया कीर , तहसील सिवनीमालवा

जिला होशंगाबाद

2. अनसुईया बाई पुत्री छारी

निवासी ग्राम नयागांव तहसील टिमरनी जिला

हरदा

3. लक्ष्मीबाई पुत्री हजारि

निवासी टांगना , तहसील इटारसी जिला -

होशंगाबाद

----- उत्तरवादी गर्ण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मओओ भूराजस्व संहिता .

माननीय अमर आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग

होशंगाबाद द्वारा रा.प्र.क्र. 284/अमील/ वर्ष 2009-10 मे

पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 जिसकी जानकारी दिनांक

09.10.17 को प्राप्त हुई एवं आदेशकी प्रमाणित प्रतिलिपि

....2

(3)

::2::


प्राप्त हुई जिसके द्वारा इस अमीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अमील निरस्त कर
निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिवनीमालवा द्वारा
राजस्व प्र.क्र. 96/बी-121 वर्ष 06-07 में पारित निर्णय दि. 21.1.09
को यथावत रखा है और अमीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अमील निरस्त की है
के विस्तृत यह अमीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता इस माननीय न्यायालय के
समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/4948

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5-3-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-8-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर की अनुमति लिये बिना प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय किया है जो मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ए) का स्पष्ट उल्लघन है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 165 के उल्लघन किये जाने के कारण प्रकरण को पुनर्विलोकन में लिया जाकर आदेश पारित फौती नामान्तरण निरस्त करते हुये पुनः जाँच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है जो विधिसंगत है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	




अध्यक्ष